

भाजपा पर तीखा प्रहार करेगा गांधी परिवार !

एनडीए सरकार को संसद से सड़क तक घेरेगी कांग्रेस

- » मनरेगा को लेकर सोनिया गांधी ने भाजपा को घेरा
 - » राहुल और प्रियंका के निशाने पर पीएम मोदी
 - » रास में बोलीं कांग्रेस सांसद- न्यूनतम मजदूरी और कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाया जाए
- ■ ■ 4पीएम न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। गांधी परिवार के मुख्य सदस्यों सोनिया गांधी, राहुल गांधी व प्रियंका गांधी ने कांग्रेस को फिर से और ताकतवर बनाने के लिए पूरी मेहनत शुरू कर दी है। इसी के महेनजर वे तीनों जहां वर्तमान में देश में शासन कर रही भाजपा सरकार को घेरने का काम करने से नहीं चूकते उसी तरह से समय-समय पर अपनी पार्टी को आईना दिखाने में भी पीछे नहीं रहते हैं।

अभी हाल ही में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुजरात दौरे में राज्य के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को अपने को बदलकर राज्य में जनता से जुड़ने को कहती रहते हैं। उधर यूपी व बिहार जैसे राज्यों में भी पार्टी ने कड़ी मेहनत शुरू कर दी है। जहां यूपी में संगठन में बदलाव करने की योजना पर काम चल रही है तो बिहार में प्रदेश अध्यक्ष को बदलकर इसकी शुरुआत कर दी गई है। इन सबके बीच तीनों ही नेताओं संसद से सड़क तक भाजपा व मोदी सरकार पर तीखे प्रहार शुरू किए हैं।

‘पीएम को रोजगार पर बोलना चाहिए था : राहुल

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी के महाकुंभ पर दिए गए कत्तव्य पर कहा कि मैं प्रधानमंत्री की बात का समर्थन करना चाहता था। कुभ हमारी परपरा है, संरक्षित है, इतिहास है। एक शिकायत थी कि प्रधानमंत्री ने जिनकी मृत्यु हुई उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दी। जो युवा कुंभ में गए उन्हें प्रधानमंत्री से रोजगार चाहिए और प्रधानमंत्री को उसपर भी बोलना चाहिए था। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेता प्रतिपक्ष को तो बोलने का मौका दिया जाना चाहिए था लेकिन नहीं देते हैं, यह नया भारत है।



मजदूरों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष ने कहा कि इस कानून को आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एवीपीएस) और राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस) सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कार्यस्थल पर कार्यरत लाभार्थियों की समय पर उपस्थिति एनएमएमएस ऐप के माध्यम से दर्ज की जाती है। गांधी ने यह भी कहा कि मजदूरी भुगतान और मजदूरी दरों में लगातार देरी

मुद्रास्फीति की भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि इन चिताओं के महेनजर कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि योजना को जारी रखने और इसका विस्तार करने के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधान किए जाएं। उन्होंने कहा, “इसके साथ ही मजदूरी में



प्रति दिन 400 रुपये की न्यूनतम वृद्धि की जाए, मजदूरी की राशि समय पर जारी की जाए, अनिवार्य एवीपीएस और एनएमएमएस आवश्यकताओं को

हटाया जाए, गरंटी वाले कार्य दिवसों की संख्या में 100 से 150 दिन प्रति वर्ष की वृद्धि की जाए।”

उन्होंने कहा, “ये उपाय यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि मनरेगा गरिमापूर्ण रोजगार और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करे।” केंद्र सरकार ने पिछले साल आम चुनावों की घोषणा से ठीक पहले, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मनरेगा मजदूरी में 3-10 प्रतिशत की मामूली वृद्धि की थी। अलग-अलग राज्यों में मजदूरी 237 रुपये (उत्तराखण्ड) से लेकर 300 रुपये (आंध्र प्रदेश) के बीच है।

विपक्ष को बोलने का नहीं दिया मौका : प्रियंका लोकसभा में महाकुंभ पर पीएम मोदी के संबोधन पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा पीएम महाकुंभ पर सकारात्मक बोल रहे थे। विपक्ष को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए था, क्योंकि विपक्ष को भी महाकुंभ के प्रति भावानाएं हैं। अगर हम अपनी बात रखते हैं तो उन्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। विपक्ष को भी दो मिनट बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए थी।

यूपी कांग्रेस में संगठन को दुरुस्त करने की तैयारी



पूरे होने पर महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी का स्वागत व सम्मान पार्टी कार्यालय पर हुआ। प्रवक्ता दीपक शर्मा ने बताया कि शमीम खां सुल्तानी सबसे अधिक समय तक इस पद पर रहे हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड दिवंगत मोहम्मद खालिद के नाम था। वह चार साल तक महानगर अध्यक्ष रहे थे। सम्मानित करने वालों में उपाध्यक्ष दिनेश यादव, महिला सभा की महानगर अध्यक्षी और सरताज गजल अंसारी व अन्य लोग मौजूद रहे।

पूरे होने पर महानगर अध्यक्ष अखिलेश सिंह ला लगातार विरोध हो रहा था। उनके ही कार्यकर्ता उनपर गंभीर आरोप लगा रहे थे। यह अन्तः विरोध काफी दिनों से चल रहा था। उनके कार्यकर्ताओं का आरोप था कि कई जगह उन्होंने पार्टी का कार्यालय और जमीन उन्होंने बेच दी। साथ ही साथ में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के साथ उनका व्यवहार भी काफी खराब थे। इसके अलावे अन्य कई कारण थे, जिस वजह से उनका लगातार विरोध हो रहा था।

शिकायतों पर राहुल और सोनिया गांधी का एवरीज

ग्रामीण गरीबों के लिए एक

महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच रहा है। उन्होंने कहा, “हालांकि यह गहरी चिंता का विषय है कि वर्तमान भाजपा सरकार ने व्यवस्थित रूप से कमजोर करने का आरोप लगाया और इस कानून के तहत न्यूनतम मजदूरी और कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाए जाने की मांग की। राज्यसभा में शून्यकाल के तहत इस मुद्दे को उठाते हुए सोनिया ने इसके लिए बजट आवंटन 86,000 करोड़

रुपये पर स्थिर बना हुआ है, जो जीडीपी के प्रतिशत के रूप में दस साल का सबसे कम प्रतिशत है।” उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति के हिसाब से देखा जाए तो प्रभावी बजट में 4,000 करोड़ रुपये की गिरावट है। उन्होंने कहा कि अनुमान है कि

आवंटित धन का लगभग 20 प्रतिशत, पिछले वर्षों से लिया गया चुकाने के लिए उपयोग किया जाएगा। पिछले साल फरवरी में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद से यह दूसरा अवसर था जब सोनिया गांधी ने शून्यकाल के दौरान कोई मुद्दा उठाया है। इससे पहले उन्होंने जल्द से जल्द जनगणना कराए जाने की मांग उठाई थी ताकि सभी पात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा कानून के तहत गारंटीकृत लाभ मिल सके। शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने यह भी कहा था कि खाद्य सुरक्षा, विशेषाधिकार नहीं बल्कि नागरिकों का एक मौलिक अधिकार है।

